

प्रेषक,

एस0 के0 दास,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

प्रेष्य,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

राज्य योजना आयोग,

देहरादून: दिनांक: 13 नवम्बर, 2007

विषय:- जिला योजना 2007-2008 की अवशेष धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने विषयक।

महोदय,

प्रायः विभिन्न समीक्षा बैठकों में यह अनुभव किया जाता रहा है कि अनुमोदित जिला योजनाओं के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति समय से जारी नहीं हो पाती है। यदि स्वीकृति जारी होती भी है तो कतिपय विभागाध्यक्षों के स्तर पर जनपदवार फॉट में विलम्ब होने के कारण संबंधित विभाग के जनपद स्तर के अधिकारी तक धनराशि नहीं पहुँचती है। इस प्रकार विकास कार्यों में विलम्ब तो होता ही है, साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों /अधिकारियों द्वारा लगातार स्वीकृति जारी करने हेतु अनुरोध किया जाता है।

सम्यक विचारोपरान्त वर्ष 2007-2008 की जिला योजना के अन्तर्गत अवशेष वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय निम्नवत् व्यवस्था लागू करने हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1- समस्त प्रशासनिक विभाग अनुमोदित जिला योजना 2007-2008 की योजनावार अवशेष धनराशि बजट प्राविधान की सीमा तक अपने जनपद स्तरीय अधिकारियों के निर्वर्तन पर तत्काल रखना सुनिश्चित करेंगे। जिसकी प्रतिलिपि जिलाधिकारियों, मण्डलायुक्त, विभागाध्यक्षों, के साथ ही साथ नियोजन/वित्त विभाग को भी पृष्ठांकित अवश्य करेंगे। जिला योजना के अन्तर्गत पूर्व में जो धनराशि विभागाध्यक्षों को जारी हुई हो तो उसकी जनपदवार फॉट कर तत्काल जनपद स्तरीय अधिकारियों को उपलब्ध करायें।

2- समस्त जनपद स्तरीय अधिकारियों के निर्वर्तन पर रखी गयी धनराशि की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति जनपद स्तर पर जिलाधिकारी जारी करेंगे।

3- रु0 50 लाख की सीमा तक की जिला सेक्टर की योजनाओं की स्वीकृति जिलाधिकारी स्तर पर जारी की जायेगी, उससे अधिक धनराशि वाली योजनाओं की स्वीकृति मण्डलायुक्त स्तर से ली जायेगी।

4- निर्माण संबंधी योजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु जनपद/मण्डल स्तर पर विभिन्न विभागों में कार्यरत अभियन्ताओं का पैनल बनाया जायेगा। यथा आवश्यकता इन अभियन्ताओं से आगणनो का परीक्षण लोक निर्माण विभाग के सिडयूल रेट के आधार पर कराकर वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी। आगणनों के परीक्षण में यह ध्यान दिया जाय कि एक विभाग के प्रस्ताव का परीक्षण इतर विभाग के अभियन्ता द्वारा कराया जाय।

5- अवस्थापना सुविधाओं यथा चिकित्सालय, विद्यालय आदि स्थापित करने विषयक जो विभागीय मानक निर्धारित हैं उनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय। मानकों में विचलन कदापि न किया जाय।

6- जिला / मण्डल स्तर पर वित्तीय स्वीकृति जारी करने, स्वीकृति / व्यय की प्रगति का संकलन, नियमित अनुश्रवण एवं प्रगति विवरण संबंधी समस्त प्रक्रिया में अर्थ एवं संख्या विभाग के जिला / मण्डल स्तरीय अधिकारी तत्सम्बन्धी पत्रावली सीधे जिलाधिकारी / मण्डलायुक्त को प्रस्तुत करेंगे।

7- जिला एवं मण्डल स्तर पर संचालित विकास कार्यों का नियमित अनुश्रवण-मूल्यांकन एवं स्थलीय सत्यापन के लिये टास्कफोर्स गठित कर सत्यापन कार्य जिलाधिकारी / मण्डलायुक्त सुनिश्चित करायेगे।

8- निर्माण कार्यों के लिये विभिन्न विभागों के कार्यरत अभियन्ताओं को सम्मिलित करते हुये "तकनीकी गुणवत्ता परीक्षण समिति" बनायी जाय जो निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करेंगी।

भवदीय,

(एस0 के0 दास)
मुख्य सचिव।

पत्राक एवं दिनांक: यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून
- 2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 3- मण्डलायुक्त गढ़वाल / कुमायूँ।
- 4- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- 5- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री के संज्ञानार्थ।
- 6- अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 7- निजी सचिव, समस्त मा0 मंत्रिगण को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
- 8- निदेशक, अर्थ एवं संख्या, देहरादून।
- 9- संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
- 10- संयुक्त निदेशक / उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या विभाग, गढ़वाल / कुमायूँ।
- 11- समस्त अर्थ एवं संख्याधिकारी, उत्तराखण्ड।
- ✓ 12- निदेशक, एन0आई0सी0, राज्य इकाई, उत्तराखण्ड।

(एस0 के0 दास)
मुख्य सचिव।